**न्यायाधीश जे. वी. गुप्ता के समक्ष**

**अनंग पाल-याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**पीरी लाल और अन्य,-उत्तरदाता।**

**सिविल संशोधन सं। 1937 सन् 1985।**

**9 सितंबर, 1985।**

सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का 5)-धारा 2 (II) और आदेश 22 नियम 5 और 10-मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में आरोपित किए जाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन-ऐसा व्यक्ति जो कथित रूप से मृतक द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर दावा करता है।- विचारण न्यायालय द्वारा खारिज आवेदन-न्यायालय का आदेश-क्या आदेश 22 के नियम 5 के अधीन पारित किया गया समझा गया है-ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील-क्या सक्षम है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 22 नियम 3, कई वादियों में से किसी एक या एकमात्र वादी की मृत्यु के मामले में विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया का उपबंध करता है।

उक्त प्रावधान के अनुसार क्या दो या दो से अधिक वादी में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित नहीं रहता है। केवल जीवित वादी या वादी, उस ओर से किए गए आवेदन पर न्यायालय, मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्षकार बनाएगा और वाद के साथ आगे बढ़ेगा। उक्त आदेश के नियम 5 में 'कानूनी प्रतिनिधि' के बारे में प्रश्नों के निर्धारण का प्रावधान है। जहां कोई व्यक्ति अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर मृतक का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके आवेदन का निर्णय संहिता के आदेश 22 नियम 10 के तहत किया गया था। यह नियम 'वाद के लंबित रहने' के दौरान किसी भी ब्याज के समनुदेशन, सृजन या हस्तांतरण पर विचार करता है और यह स्पष्ट है कि यदि कोई मामला संहिता के आदेश 22 नियम 3 के तहत आता है, तो उसका नियम 10 आकर्षित नहीं होगा। आदेश 22 का नियम 10 पूरी तरह से अलग स्थिति में और कानूनी प्रतिनिधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है। मान लीजिए कि मृतक का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले आवेदक के पक्ष में वाद के लंबित रहने के दौरान कोई समनुदेशन, सृजन या किसी भी ब्याज का हस्तांतरण नहीं है। उनके आवेदन को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को आदेश 22 नियम 10 के तहत पारित नहीं कहा जा सकता था, बल्कि इसे नियम 5 के तहत पारित किया गया था और इसलिए, इसके खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं थी।

(पैरा 3) धारा 115 C.P.C. के अधीन याचिका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 44 में यह प्रार्थना की गई है कि पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार किया जाए, निचली अपीलीय अदालत

के आदेशों को दरकिनार किया जाए और प्रतिवादी प्यारे लाल के आवेदन को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेशों को बहाल किया जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय का तरीका कृपया मामले के तथ्य और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उचित आदेश को पारित करे।

याचिकाकर्ता की ओर से सुरेश अंबा, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर से श्री राम रंग, अधिवक्ता।

**आदेश**

1. साहिब दयाल और अन्य ने 20 जुलाई, 1982 को घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा देने के लिए मुकदमा दायर किया। उक्त मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, वादी में से एक साहिब दयाल की 28 सितंबर, 1982 को मृत्यु हो गई। पियरे लाल, प्रतिवादी ने उन्हें अपने कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकॉर्ड पर लाने के लिए 21 दिसंबर, 1983 को आवेदन दायर किया। इसमें यह आरोप लगाया गया था कि साहिब दयाल की मृत्यु हो गई, उन्होंने मुकदमे में जमीन के संबंध में 2 मई, 1978 की वसीयत को अपने पक्ष में पंजीकृत करा लिया। इसलिए, वह उनका कानूनी प्रतिनिधि था और इस प्रकार रिकॉर्ड पर लाए जाने का हकदार था। आवेदन में प्रतिवादियों की ओर से अन्य बातों के साथ-साथ पियरी लाल की दलील पर भी प्रतिवाद किया गया था। प्रतिवादी उसका कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, न ही उसके द्वारा उसके पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की गई थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। ट्रायल कोर्ट ने वसीयत दिनांक के आधार पर आवश्यक मुद्दा तय किया कि क्या पीयर लाल मृतक साहिब दयाल का कानूनी उत्तराधिकारी था। 2 मई 1978, जैसा कि आरोप लगाया गया। अंततः, यह पाया गया कि उक्त साहिब दयाल द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में वसीयत का निष्पादन साबित नहीं हुआ था और इस प्रकार, आवेदक पियरे लाल, मृतक का कानूनी उत्तराधिकारी नहीं बन गया, जैसा कि दावा किया गया है। परिणामस्वरूप उनके द्वारा दायर आवेदन को आदेश दिनांक द्वारा खारिज कर दिया गया। 6 अक्टूबर, 1984. इससे असंतुष्ट पियरी लाल ने अपील दायर की। उसमें, प्रतिवादियों की ओर से एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई थी कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश आदेश XXII, R. 5 सिविल पीसी जिसे इसके बाद कोड कहा जाता है) के तहत था और इस प्रकार, इसके खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं थी। उनके लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में जाना था। पियरी लाल की ओर से यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा आदेश कोड के आदेश XXII, R. 10 के तहत पारित किया गया है और इस प्रकार, कोड के आदेश XLIII, R. 1 के तहत अपील की परिकल्पना की गई थी। विद्वान निचली अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को संहिता के आदेश XXII, R. 10 के तहत पारित माना जाएगा और इसलिए, अपील कायम रखने योग्य थी। गुण-दोष के आधार पर, इसने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलट दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वसीयत का निष्पादन विधिवत साबित हुआ था और पीयर लाल मृतक साहिब दयाल के कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में पक्षकार बनने का हकदार था। इससे असंतुष्ट प्रतिवादी ने इस न्यायालय में यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है।

2. इस पुनरीक्षण याचिका में पक्षों के बीच मुख्य विवाद यह है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा मृतक साहिब दयाल के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में पियरे लाल के आवेदन को खारिज करने का आदेश अपील योग्य था या नहीं।

3. इसमें कोई विवाद नहीं है कि यदि उक्त आदेश को संहिता के ओ. , आर. 10 तो वहां से अपील सक्षम थी। संहिता का आदेश XXII, R. 3, कई वादी में से किसी एक या एकमात्र वादी की मृत्यु के मामले में कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर

लाने के लिए एक आवेदन की प्रक्रिया प्रदान करता है। उक्त प्रावधान के अनुसार जहां दो या दो से अधिक वादी में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित वादी या वादी के पास नहीं रहता है, उस संबंध में किए गए आवेदन पर न्यायालय, मृत वादी के कानूनी प्रतिनिधि को बुलाएगा। एक पार्टी बना ली है और मुकदमा आगे बढ़ाएंगे। उक्त आदेश के नियम 5 में कानूनी प्रतिनिधि के रूप में प्रश्नों के निर्धारण का प्रावधान है। शब्द "कानूनी प्रतिनिधि" को संहिता की धारा 2(11) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका निम्नलिखित प्रभाव है, -

"'कानूनी प्रतिनिधि" का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो कानून में किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल होता है जो मृतक की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है और जहां एक पक्ष प्रतिनिधि चरित्र में मुकदमा करता है या मुकदमा दायर करता है, वह व्यक्ति जिस पर संपत्ति हस्तांतरित होती है पार्टी की मृत्यु पर मुकदमा या मुकदमा किया जाएगा।"

आवेदन दिनांक में दिए गए कथन से। 21 दिसंबर, 1983 को पियरे लाल द्वारा दायर, यह स्पष्ट है कि उन्होंने 2 मई, 1978 को उनके पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर खुद को मृतक साहिब दयाल का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा किया था। इन तथ्यों पर, प्रतिवादी पियरे लाल की ओर से यह सफलतापूर्वक तर्क नहीं दिया जा सका कि इस आवेदन का निर्णय संहिता के आदेश XXII, R. 10 के तहत किया गया था। उक्त आदेश के नियम 10(1) में लिखा है,--

"10. मुकदमे में अंतिम आदेश से पहले समनुदेशन के मामले में प्रक्रिया। (1) किसी मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी हित के समनुदेशन, सृजन या हस्तांतरण के अन्य मामलों में, न्यायालय की अनुमति से मुकदमा जारी रखा जा सकता है या उस व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर या जिस पर ऐसा हित आया है या हस्तांतरित किया गया है।"

उपर्युक्त नियम "मुकदमे की लंबितता" के दौरान किसी भी हित के असाइनमेंट, निर्माण या हस्तांतरण पर विचार करता है और यह स्पष्ट है कि यदि कोई मामला आदेश XXII के अंतर्गत आता है। संहिता का आर.3, फिर उसका आर.10 आकर्षित नहीं होगा। आदेश XXII का नियम 10 पूरी तरह से अलग स्थिति और कानूनी प्रतिनिधि के अलावा अन्य व्यक्तियों पर लागू होता है। माना जाता है कि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी पियरे लाल के पक्ष में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किसी भी हित के हस्तांतरण का कोई असाइनमेंट नहीं था। बल्कि उसने खुद को मृतक साहिब दयाल का कानूनी प्रतिनिधि होने का दावा किया। इस मामले में निचली अपीलीय अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण गलत और गलत धारणा वाला था। ट्रायल कोर्ट के आदेश को संहिता के आदेश XXII, R. 10 के तहत पारित नहीं कहा जा सकता है; बल्कि इसे आदेश XXII, R. 5 के तहत पारित किया गया था और इसलिए, इसके खिलाफ कोई अपील सुनवाई योग्य नहीं थी।

4. ऊपर दर्ज कारणों से, यह पुनरीक्षण याचिका सफल होती है और अनुमति दी जाती है। निचली अपीलीय अदालत के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया है और निचली अदालत द्वारा मृतक साहिब दयाल के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में उसे रिकॉर्ड पर लाने के प्रतिवादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया था, जिसे लागत के साथ बहाल किया गया है। पक्षों को 10 अक्टूबर 1985 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

5. संशोधन की अनुमति.

***अस्वीकरण:*** *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा